

प्रश्नकाल

प्रदेश सरकार ने बीते दो वर्षों में राजधानी शिमला में 66 भवनों को असुरक्षित घोषित किया है, जिनमें आवासीय भवनों के साथ सरकारी कार्यालय भी शामिल हैं। शिमला में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन आज प्रश्नकाल के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यह जानकारी दी। विधायक विपिन सिंह परमार के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके पास फिलहाल कर्मचारियों का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसे कर्मचारियों के लिए आवास की अलॉटमेंट करने के निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग जी.ए.डी. को जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि शिमला में स्थित विधायक सदन मेट्रोपोलिस को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस भवन के मरम्मत कार्य के लिए बजट भी निर्धारित कर दिया गया है। सुखविन्द सिंह सुक्खू ने आश्वासन दिया कि असुरक्षित भवनों में रह रहे सभी कर्मचारियों को अगले दो महीनों के भीतर वैकल्पिक आवास उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में कहा कि सरकार का धर्मशाला में प्रदेश हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने का फिलहाल कोई विचार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण स्थापित करने की प्रक्रिया जारी है।

प्रश्नकाल-2

विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत पिछले 2 वर्षों में कुल 8 हजार एक सौ 55 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में 3 हजार 7 सौ 30 और 2024-25 में 4 हजार 4 सौ 25 लाभार्थियों को लाभ मिला है। विधायक डॉक्टर जनक राज के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग फोरलेन बनेगा और आठ पैकेज में इसका निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय उच्च मार्ग को फोरलेन बनाने संबंधी डी.पी.आर. तैयार की जा रही है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि नेशनल हाई वे अथॉरिटी को राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए लेकिन एन.एच.ए.आई. ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही है और इस बारे में वे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बात करेंगे।

महंगाई भत्ता

केंद्र सरकार ने केन्द्रीय कर्मियों के लिए दो प्रतिशत महंगाई भत्ता और पेंशनभोगियों को महंगाई राहत को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह वृद्धि इस साल की पहली जनवरी से लागू होगी और इससे केंद्र सरकार के 48 लाख 66 हजार कर्मचारियों व 66 लाख 55 हजार पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

युवा संसद

नेहरू युवा केंद्र संगठन शिमला द्वारा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 'विकसित भारत युवा संसद-2025' का आयोजन किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज इस कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। राज्यपाल ने कहा कि युवाओं को किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति माना जाता है और उनकी ऊर्जा, विचार व नवाचार समाज को नई दिशा देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश 'विकसित भारत' के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस यात्रा में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल ने केन्द्र सरकार के कार्यों की सराहना करते हुए प्रतिभागियों को राष्ट्र के सक्रिय और सतर्क युवा के रूप में राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए प्रेरित किया। इस राज्यस्तरीय युवा संसद कार्यक्रम में पहले दिन विभिन्न जिलों के 32 प्रतिभागियों ने भारतीय संविधान की 75 साल की यात्रा पर अपने विचार प्रस्तुत किए।

सिकंदर कुमार

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि केंद्र द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के तहत मदद प्रदान की गई है। सांसद सिकंदर कुमार के सवाल के जवाब में सदन में उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य प्रासंगिक अवसंरचना के विकास के माध्यम से राज्य व संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुदृढ़ करना है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता योजना के तहत वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान दी गई राशि का ब्यौरा भी सदन में रखा।

प्रतिभा सिंह

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने युवाओं में बढ़ते नशे पर चिंता जताते हुए इसके खिलाफ सभी से एकजुट होने का आहवान किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार नशे के खात्मे के लिए प्रतिबद्ध है और नशे की तस्करी और मादक पदार्थों के कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने अब सख्त कानून बनाया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नशे जैसे विषय पर राजनीति करने की बजाए युवाओं को इसके दुष्प्रभाव के प्रति जागरूक करने के लिए साझे प्रयासों की जरूरत है।

मिल्क फ़ैडरेशन

कुल्लू ज़िला के बजौरा मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया जाएगा जिसमें प्रतिदिन 20 हजार लीटर से अधिक दूध एकत्रित किया जाएगा। हिमाचल मिल्क फ़ैडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष बुद्धिसिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक हजार एक सौ 50 से अधिक दूध उत्पादन समितियां काम कर रही हैं जिन्हें और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। बुद्धिसिंह ने कहा कि बजौरा में प्रोसेसिंग प्लांट खुलने से जहां दूध उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी वहीं युवाओं को भी रोजगार के अवसर मिलेंगे।
